

देयता प्रबंधन में चुनौतियां: संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता*

एम. राजेश्वर राव

सबसे पहले मैं मिंट बीएफएसआई शिखर सम्मेलन और पुरस्कार के इस 17वें संस्करण में मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ जुड़ने का यह अवसर मिला है जिससे मुझे खुशी हो रही है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विनियामक के रूप में मैंने सोचा कि विनियमित संस्थाओं की देनदारियों के प्रबंधन और चुनौतियों पर बात करने का यह अवसर है क्योंकि यह कम चर्चित विषय है। जमा और ऋण वृद्धि के बीच बेमेल विशेष टिप्पणी करते हुए गवर्नर दास ने पहले इस क्षेत्र में बढ़ती चुनौती की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। इसलिए, आपके विचार के लिए कुछ मुद्दों पर बात करूंगा।

परिचय

बैंकिंग का मुख्य कार्य है जमा राशियां स्वीकार करना है, जो आम तौर पर अल्पकालिक होती हैं, और ऋणों को वित्तपोषित करना, जिनकी परिपक्वता अवधि आम तौर पर लंबी होती है। इस प्रकार परिपक्वता रूपांतरण (मॅचुरिटी ट्रांसफॉर्मेशन) वित्तीय मध्यस्थता की एक अंतर्निहित विशेषता है और बैंक इससे जुड़े जोखिमों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। नतीजतन, बेहतर लाभप्रदता प्राप्त करने, चलनिधि में सुधार करने और बैंक को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए आस्तियों और देनदारियों का रणनीतिक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से, बेसल I और II सहित विनियामक ढांचे ने तुलनपत्र के आस्तिक पक्ष पर अधिक जोर दिया है, जो ऋण जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता पर केंद्रित है। इस पर अधिक जोर इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि ऋण चूक और आस्तिक मूल्य में गिरावट बैंक की ऋण शोधन क्षमता के लिए मुख्य खतरे होते हैं। चलनिधि और वित्त पोषण जोखिम, जो मुख्य रूप से देनदारियों से उत्पन्न होते हैं, को बड़े पैमाने पर एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा जाता था कि बैंक किसी भी विनियामक निरीक्षण और हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना खुद प्रबंधन कर सकते हैं।

* 17 जनवरी 2025 को मुंबई में मिंट वार्षिक बीएफएसआई शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। अखिलेश गोखले, टोनी मैमन और शशांक श्रीवास्तव द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान बैंकों को तुलनपत्र के दोनों तरफ की कमजोरियों का सामना करना पड़ा, जिसने उक्त दृष्टिकोण को चुनौती दी, और जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के विनियामक ढांचे में भारी बदलाव हुआ। इस संकट के दौरान कई बैंकों को, पूंजी आवश्यकताओं का पालन करने के बावजूद, दिवालिया होने के कारण चलनिधि संकट का सामना करना पड़ा, जिससे अल्पकालिक देयताओं पर निर्भर रहने की कमजोरी उजागर हुई। इसने आस्तिक-पक्ष की कमजोरियों के अलावा चलनिधि प्रबंधन के प्रणालीगत महत्व और विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह नीतिगत प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसके कारण चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) जैसे व्यापक वैश्विक चलनिधि मानकों का निर्धारण हुआ जो अल्पकालिक और मध्यम अवधि की चलनिधि की समुत्थाशीलता को लक्षित करते हैं।

अब यह माना हुआ तथ्य है कि देयता प्रबंधन न केवल एक विनियमित इकाई (आरई) की स्थिरता और शोधन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूंजी और संवृद्धि दिशापथ (ट्राजेक्ट्री) पर उसके प्रतिलाभ को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। अर्जन के नजरिए से, ऋण पर अर्जित ब्याज का स्प्रेड और निधियों की लागत बैंक की निवल आय और लाभप्रदता निर्धारित करती है।¹ इस प्रकार देयताओं की लागत का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और अर्जन अनुपात पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुल जमा में चालू और बचत खाता (सीएसए) जमा का हिस्सा, खुदरा बनाम थोक वित्तपोषण का मिश्रण और देयताओं की अवधि वित्तपोषण लागत, और परिणामस्वरूप बैंकों की लाभप्रदता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, किसी भी संकट के दौरान वित्तपोषण की स्थिरता होना समुत्थाशीलता की कुंजी है। इस संदर्भ में, मैं भारत में देयता प्रबंधन के उद्भव, देयता संरचना में बदलते रुझान, इकाई-विशिष्ट चुनौतियों और विनियामक अपेक्षाओं पर संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा।

भारत में एएलएम का उद्भव

जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1990 के दशक के व्यापक आर्थिक सुधारों के साथ भारतीय बैंकिंग में रणनीतिक परिवर्तन हुआ। ब्याज दरों के अविनियमन और वैश्विक एकीकरण में वृद्धि

¹ लाभ का दूसरा मुख्य चालक प्रावधान आवश्यकता है जो आस्तिक की गुणवत्ता पर निर्भर है।

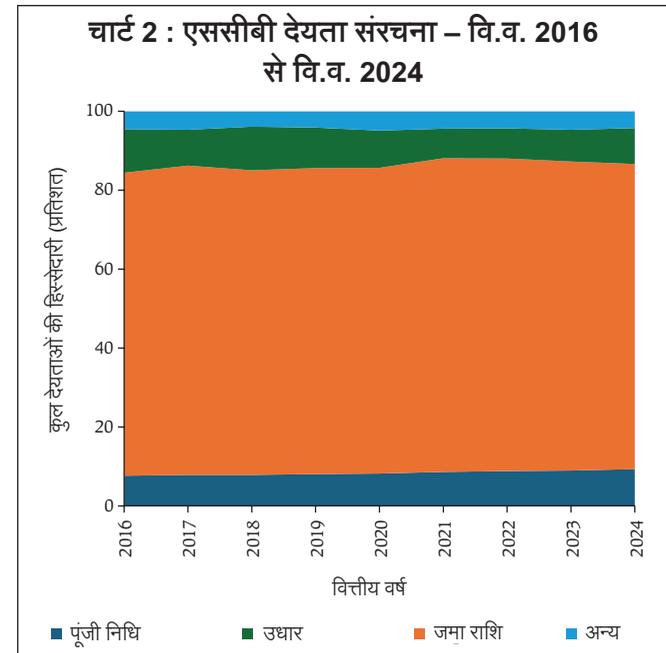
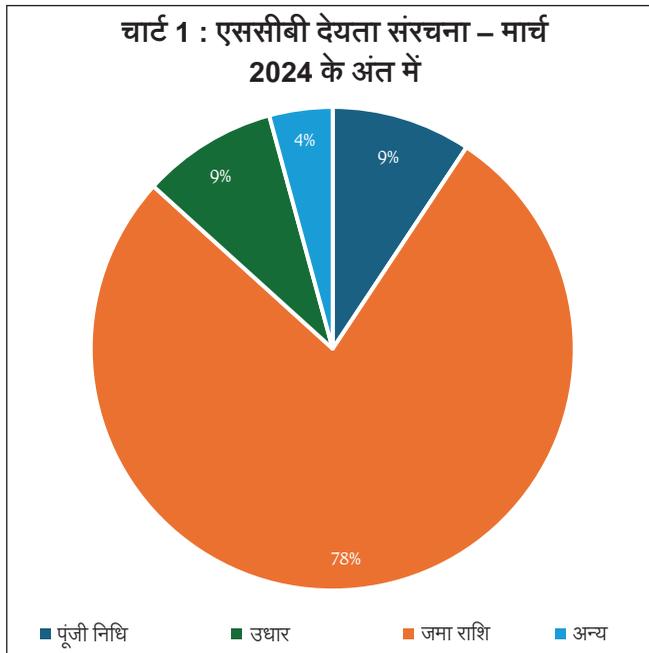
ने वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को और अधिक जटिल और बड़ा बना दिया, जिसके लिए रणनीतिक प्रबंधन की आवश्यकता थी। तदनुसार, वित्तीय संस्थानों के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) पर दिशानिर्देश पहली बार फरवरी 1999 में जारी किए गए, जिसमें 2000 के दशक के अंत में और भी प्रावधान किए गए, जिसमें विवेकपूर्ण सीमाओं और प्रकटीकरण ढांचे के साथ ब्याज दर और चलनिधि जोखिम शामिल थे।

भारतीय विवेकपूर्ण ढांचे ने 2012 में 'सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति' (बीसीबीएस) के सिद्धांतों को शामिल किया, जिसके बाद वित्तपोषण चलनिधि के लिए दो न्यूनतम मानकों - एलसीआर और एनएसएफआर को अपनाया गया। यह देखते हुए कि एलसीआर व्यवस्था इंटर्राडे चलनिधि पर नज़र नहीं रख पा रही है और वित्तीय प्रणाली के भीतर बढ़ती अंतर-निर्भरताएं भुगतान और निपटान प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली चलनिधि बाधाओं को जन्म दे सकती हैं, इंटर्राडे चलनिधि की निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। संकेन्द्रण जोखिम को कम करने और बड़े बैंकों की अनियंत्रित देयता के प्रणालीगत प्रभावों को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बहुत पहले ही वाणिज्यिक बैंकों (2007) के लिए अंतर-बैंक

देयताओं (आईबीएल) पर सीमाएँ और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) (2009) के लिए अंतर-बैंक जमा सीमाएँ निर्धारित कर दी थीं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आईबीएल के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कॉल और नोटिस मनी मार्केट में उधार लेने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएँ निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। ऐसी देयता-आधारित संकेन्द्रण सीमाएँ भारत के संबंध में अनोखी हैं जो इन जोखिमों के प्रति रिज़र्व बैंक की पूर्व जागरूकता को दर्शाती हैं।

देयता का स्वरूप और संवृद्धि

एससीबी के लिए जमा राशि प्राथमिक स्रोत अभी भी बनी हुई है, जिसकी राशि 217 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2024 के अंत में कुल देनदारियों का 77 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, पूंजीगत निधि (यानी, पूंजी, रिज़र्व और अधिशेष) और उधार, देनदारियों का लगभग 9-9 प्रतिशत है²। वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2024 के बीच के आंकड़ों की तुलना यह दर्शाती है कि जमा राशि लगभग 10 प्रतिशत की वार्षिक दर³ से बढ़ी है जो समग्र तुलनपत्र की वृद्धि के समरूप है, और कुल देनदारियों में उनका योगदान लगभग 77 प्रतिशत पर स्थिर रहा है (चार्ट 1 और 2⁴)। इस बीच, उधार 7 प्रतिशत की धीमी दर से बढ़ा है जिसके



² उधार में अन्य बातों के अलावा आरबीआई, अन्य बैंकों, संस्थानों और एजेंसियों, पूंजीगत साधनों (स्थायी ऋण साधन और टियर 2 ऋण) और अन्य बांड तथा डिबेंचर से उधार शामिल हैं। शेष देनदारियों (4.2 प्रतिशत) में अन्य देनदारियां और प्रावधान शामिल हैं।

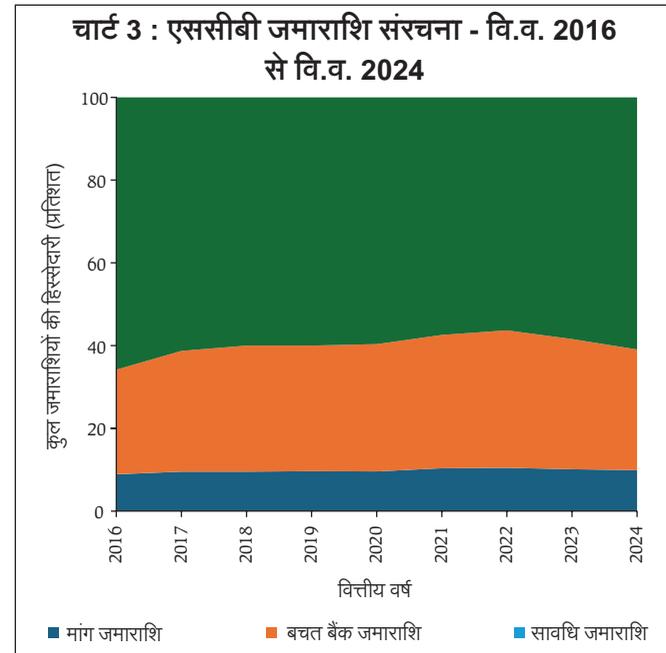
³ संघयी वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर)।

⁴ स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट, 2016 से 2024।

परिणामस्वरूप कुल देनदारियों में इसकी हिस्सेदारी 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर, पूंजी निधि में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा इसका हिस्सा 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है, जो बैंकों के तुलनपत्र में सुधार दर्शाता है, जिसे उच्च लाभप्रदता तथा पूंजी जुटाने के प्रयासों से बढ़ावा मिला है।

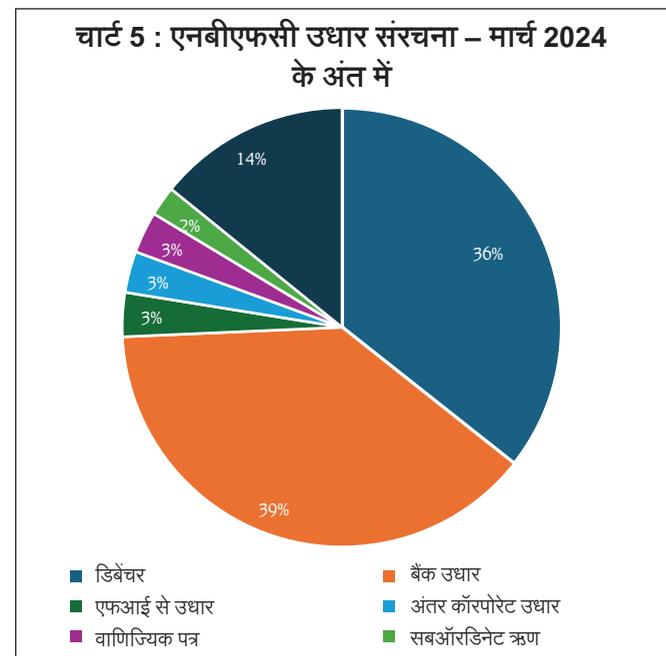
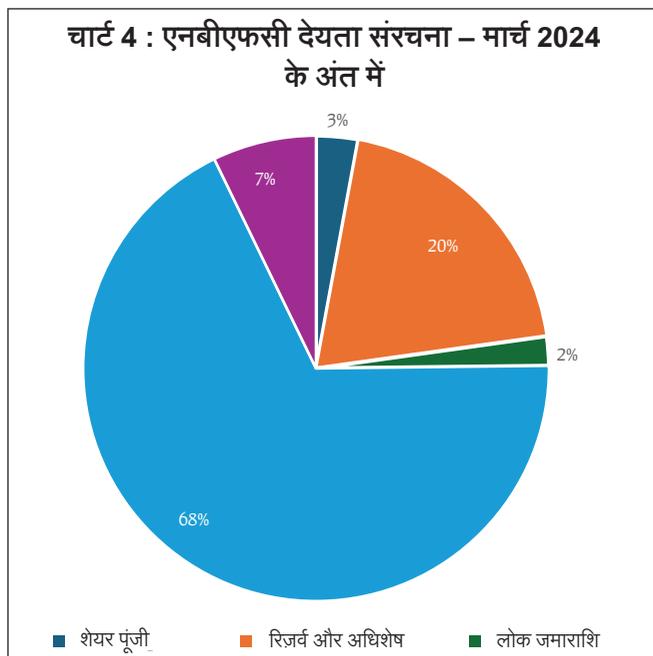
परिपक्वता के लिहाज से, इसी अवधि के दौरान, सावधि जमा का योगदान कुल जमा के 65.8 प्रतिशत से घटकर 60.9 प्रतिशत हो गया है, जबकि बचत और चालू खाता जमा का हिस्सा क्रमशः 25.3 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 29.2 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत हो गया है। नतीजतन, सीएसए अनुपात 34.2 प्रतिशत से बढ़कर 39.1 प्रतिशत हो गया है। इस प्रवृत्ति से एससीबी के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार हुआ होगा, जो वित्त वर्ष 2015-16 के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3⁵)।

जमाराशियों के अलावा, बैंक अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बॉण्ड और टियर 2 बॉण्ड जैसे ऋण पूंजी साधनों के रूप में उधार राशि जुटाते हैं। इसके अलावा, बैंकों को बुनियादी ढांचे और किफायती आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए घरेलू दीर्घकालिक बॉण्ड



जारी करने की अनुमति है और वे ईसीबी मार्ग के तहत विदेशी बाजारों में भी धन जुटा सकते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए, उधार राशियां वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो मार्च 2024 के अंत तक 34.46 लाख करोड़ रुपये या कुल देनदारियों का 68 प्रतिशत था। उधारी के भीतर, डिबेंचर और बैंकों से लिया गया उधार का अंश प्रमुख है (चार्ट 4 और 5⁶)। यह स्थिति



⁵ स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट, 2016 से 2024।

⁶ स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट 2023-24।

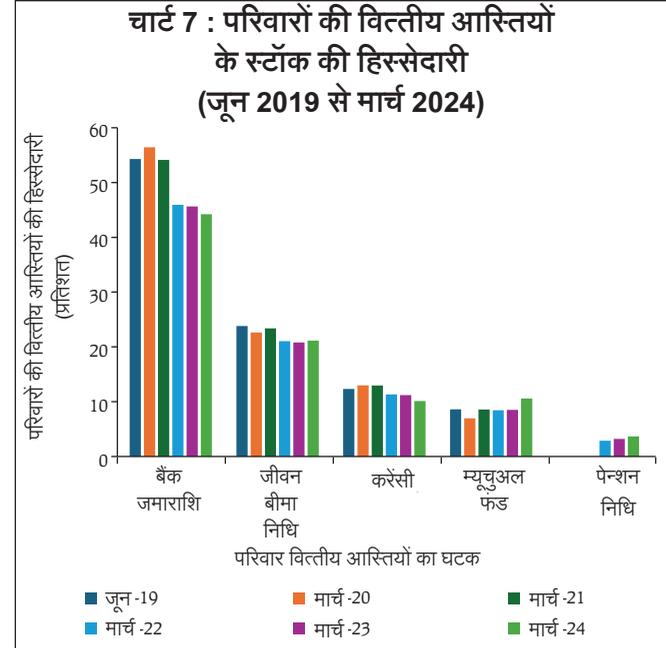
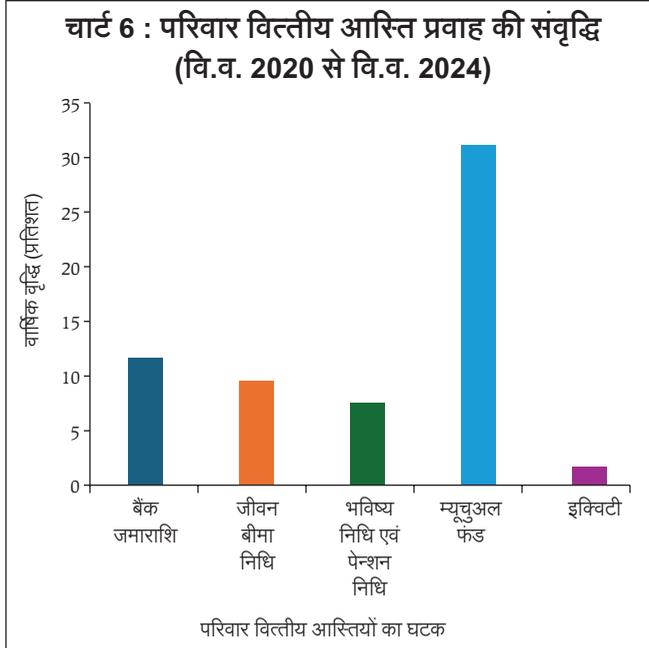
एनबीएफसी की देनदारियों को बैंकों की तुलना में अधिक बाजार संचालित और ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

बदलते रुझान और चुनौतियाँ

बैंक घरेलू बचत, जो वर्तमान में भारत की सकल बचत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, को प्रयोग में लाते हुए अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में सबसे आगे हैं। हाल के रुझान बताते हैं कि परिवारों के बचत माध्यम अब बदल रहे हैं। वे बचत के लिए पारंपरिक बैंक जमाओं को छोड़ पूंजी बाजार आस्तियों की ओर जा रहे हैं (चार्ट 6 और 7)। यह बदलाव कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र को सघन करने के लिए लक्षित प्रयास, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वृद्धि, जो पूंजी बाजारों तक सुविधाजनक और बाधा रहित पहुंच प्रदान करता है, जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण निवेश वरीयताओं में बदलाव, वित्तीय जागरूकता में वृद्धि और हाल की अवधि में इक्विटी बाजारों द्वारा दिए गए निरंतर उच्च प्रतिलाभ शामिल हैं। इसके अलावा, वैकल्पिक आस्ति वर्गों का उदय, उच्च प्रतिफल

की खोज और पोर्टफोलियो विविधीकरण ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है। पिछले दशक में⁸, म्यूचुअल फंड, पेंशन और भविष्य निधि, तथा बीमा कंपनियों के ग्राहकों और प्रबंधन के तहत आस्तियों (एयूएम) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रवृत्ति आगे और भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि यह प्रवृत्ति बैंकों के लिए उपलब्ध समग्र निधि को नहीं बदलेगी, लेकिन यह बैंकों के लिए निधि की लागत और मार्जिन पर प्रभाव डालने वाली जमाओं के स्वरूप को बदल सकती है।

जैसा कि पहले बताया गया है, हालांकि सीएएसए जमाराशियों में लंबी अवधि में सुधार हुआ है, लेकिन हाल में एक बदलाव यह है कि सीएएसए जमाराशियों का हिस्सा घट रहा है और सावधि जमाराशियों, विशेष रूप से उच्च ब्याज दर वाली जमाराशियों का हिस्सा बढ़ रहा है⁹ इसका बैंकों के एनआईएम और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ता है। हाल ही में बैंकों ने जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के माध्यम से अल्पावधि निधि पर अपनी निर्भरता भी बढ़ा दी है और औसत सीडी बकाया 2012¹⁰ के स्तर पर पहुंच गया है। तथापि, बैंकों को इस तथ्य को संज्ञान में लेना चाहिए कि यदि बाजार की



⁷ स्रोत: आरबीआई क्वार्टरली डेटा रिलीज़ ऑन हाउसहोल्ड फिनान्शियल सेविंग्स, आरबीआई स्टाफ गणना। टिप्पणी: (i) चार्ट 6 और 7 में घरेलू वित्तीय आस्तियों के चुनिंदा घटक शामिल हैं; (ii) चार्ट 6 घरेलू वित्तीय आस्तियों के प्रवाह का सीएजीआर प्रदान करता है।

⁸ उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड उद्योग का एयूएम 2014 के ₹10 ट्रिलियन से बढ़कर 31 दिसंबर 2024 तक ₹66.93 ट्रिलियन हो गया है, जो 10 वर्षों में 6 गुना से अधिक की वृद्धि है। 31 दिसंबर 2024 तक खातों/फोलियो की कुल संख्या 22.50 करोड़ थी। [स्रोत: एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (एएमएफआई) वेबसाइट]

⁹ सावधि जमा राशि 2024-25 की पहली छमाही में जुटाई गई वृद्धिशील जमा राशि का 82 प्रतिशत है। स्रोत: आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2024।

¹⁰ वित्त वर्ष 2023-24 में औसत बकाया सी.डी. 4.18 लाख करोड़ रुपये थी। स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर.बी.आई. डेटाबेस (डी.बी.आई.ई.), आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

स्थिति बिगड़ती है तो अल्पावधि देनदारियों पर अधिक निर्भरता के अपने दुष्परिणाम हो सकते हैं।

बैंक अपनी प्रतिस्पर्धी ताकत, बाजार स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर देयता राशि जुटाने के लिए अलग-अलग रणनीतियों को अपनाते हैं। बहुत अधिक शाखाओं वाले बड़े बैंकों के पास कम लागत वाली, स्थिर स्वरूप की खुदरा जमा उपलब्ध हो सकती है। जबकि अधिकतर शहरी उपस्थिति वाले बैंक उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए उच्च-मूल्य वाले जमा उत्पाद उपलब्ध कराकर समृद्ध ग्राहक वर्ग को लक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने वाले कुछ बैंक ग्राहक बढ़ाने और जमा राशि प्राप्त करने के स्रोतों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हैं, जिससे उन्हें खुदरा और कॉरपोरेट जमा, दोनों को आकर्षित करने में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। दूसरी ओर, विशेष-कार्य बैंकों की अन्य बैंकों से जमा प्राप्त करने और थोक वित्तपोषण पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है। निधि संबंधी प्रोफाइल में यह विविधता एएलएम में अलग प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करती है, क्योंकि चलनिधि प्रबंधन, निधि लागत, और जोखिम प्रबंधन प्रत्येक व्यावसायिक रणनीति में अपनी-अपनी जटिलताएं होती हैं।

जमाराशियों का 'संस्थागतीकरण', जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, बैंकों के लिए एएलएम की दृष्टि से विशिष्ट चुनौतियाँ लेकर आया। खुदरा जमाराशियों पर निर्भरता में कमी करने और संस्थागत स्रोतों से अधिक वित्त प्राप्त करने से निधि लागत में वृद्धि होने की संभावना होगी, जो बदले में लाभप्रदता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। मार्जिन को बनाए रखने के प्रयास में इस बढ़ी हुई निधि लागत का असर अंततः दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज दर पर हो सकता है। इससे या तो दिया जाने वाले ऋण की वृद्धि बाधित होगी या ऋणदाता अंडरराइटिंग मानकों को कम करने, और आय अनुपात बनाए रखने के लिए, जोखिम भरे उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बैंकों को ऐसी कुछ प्रथाओं के जोखिमों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो मजबूत आर्थिक विकास के दौरान कम महत्वपूर्ण लग सकते हैं लेकिन जो आर्थिक मंदी के दौरान गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। जो बैंक थोक वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भर हैं वे आर्थिक तनाव के समय जोखिमों के प्रबंधन और बहिर्वाहों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए, इन जोखिमों को कम करने के लिए देयता का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

कुछ बैंकों से संबंधित एक अन्य मुद्दा यह है कि उनकी जमा वृद्धि उनकी ऋण वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पा रही है। इसके कारण ऋण वितरण के लिए थोक वित्तपोषण पर अधिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों के बारे में विनियामक चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। इस तरह के असंतुलनों को संभावित संरचनात्मक चलनिधि कमजोरियों के संकेतक के रूप में देखा जाता है। जबकि विनियामक बैंकिंग क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करने के लिए एक व्यापक आर्थिक पैमाने के रूप में इन प्रवृत्तियों की निगरानी करते हैं, यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत बैंकों के लिए ये संकेतक अकेले चलनिधि जोखिम को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त हैं। अल्पकालिक चलनिधि के दृष्टिकोण से एलसीआर जैसे साधन जमाराशि संबंधी स्थिरता, जमाकर्ता व्यवहार और खुदरा तथा थोक निधि के बीच अंतर-संबंध जैसे कारकों को विचार में लेते हुए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन संकेतकों के बीच संबंध बहुआयामी और अक्सर विरोधाभासी होते हैं, जिससे किसी एक माप पर अकेले भरोसा न करके बैंकों की एएलएम प्रोफाइल का समग्र मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।

बैंकों के विपरीत, एनबीएफसी¹¹ की देयता प्रोफाइल, उनकी प्राथमिक गतिविधियों, विनियामक आवश्यकताओं और उनके द्वारा वित्तपोषित आस्तियों के प्रकारों द्वारा तय होती है। ऐतिहासिक रूप से यह पाया गया है कि एनबीएफसी की बुनियादी ढांचे और आवास ऋण जैसी दीर्घकालिक आस्तियों का समर्थन करने के लिए अल्पकालिक निधि पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप संकट समय में चलनिधि की बड़ी कमी, निवेशकों के विश्वास में गिरावट और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट हो सकती है, जिससे पूंजी बाजारों से ऋण प्राप्त करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है। नतीजतन, एनबीएफसी प्रत्यक्ष उधार और बैंकों द्वारा डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की खरीद, दोनों स्वरूपों की बैंक निधि पर बहुत अधिक निर्भर हो गए, जिससे निधि का संकेंद्रण हुआ है। बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता को पहचानते हुए, रिजर्व बैंक ने नवंबर 2023 में एनबीएफसी के प्रति बैंक एक्सपोजर के जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंकों तक बढ़ा दिया, जिससे एनबीएफसी द्वारा लिए जाने वाले बैंक उधार में व.द.व वृद्धि को कम करने में मदद मिली है। इस कमी को पूरा

¹¹ रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं का एक समूह है जो विविध व्यावसायिक रणनीतियों के साथ काम करती हैं, जैसे कि निवेश ऋण, बुनियादी ढांचा वित्त, सूक्ष्म वित्त, फेक्ट्रिंग, कोर निवेश, आवास वित्त, नॉन-ऑपरेटिव फिनान्शियल होल्डिंग, खाता समाहर्ता, पीयर-टू-पीयर उधार और प्राथमिक डीलिंग गतिविधियाँ।

करने के लिए एनबीएफसी ने सीपी¹² और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)¹³ के माध्यम से निधि संग्रहण को बढ़ा दिया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनने से एनबीएफसी की घरेलू बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम हो सकती है और उन्हें निधि के लिए अधिक विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें अतिरिक्त जोखिम भी उठाना पड़ सकता है, खास तौर पर असुरक्षित (अन-हेज्ड) मुद्रा से संबंधित जोखिम, जिससे निधि लागत में अस्थिरता और विनियम दर में उतार-चढ़ाव के कारण संभावित चलनिधि तनाव हो सकता है। एनबीएफसी को चाहिए कि वे अपने एएलएम ढांचे में विदेशी मुद्रा हेजिंग को जोड़ें और निधि लागत में अस्थिरता को कम करने के लिए मुद्रा जोखिम पर बारीकी से नज़र रखें। उधार देने के उद्देश्य से संसाधनों को मुक्त करने के लिए प्रतिभूतिकरण के माध्यम से आस्तियों का चलनिधि परिवर्तन भी एएलएम संरचना को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम कर सकता है।

विनियामक अपेक्षाएँ

अब मैं कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिन पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा अपनाई गई एएलएम प्रथाओं और इन मुद्दों पर विनियामक अपेक्षाओं के बारे में विश्व स्तर पर व्यापक रूप से बहस हो रही है।

सबसे पहले, बैंकिंग में नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के उदय ने निधि उपलब्धता और नकदी प्रवाह को प्रबंधित करने में उपभोक्ता के लिए कई विकल्प उपलब्ध करा दिए हैं जिससे ग्राहक व्यवहार में काफी बदलाव आया है। इसके अलावा, पारंपरिक और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसार के बदलते स्वरूप ग्राहक व्यवहार को बड़े पैमाने में प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संकट संभावित रूप से बढ़ सकता है और तीव्र हो सकता है। ये कारक बढ़ी चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः बैंकों को सतर्क रहने और जमाराशि की स्थिरता और ग्राहक व्यवहार पर अपनी मॉडलिंग व्यवस्था की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि जमाराशि बनाए रखने, निकासी के स्वरूप, पूर्व-भुगतान और ब्याज दर संवेदनशीलता का बेहतर अनुमान लगाया जा सके।

दूसरा, यू.के. में देयता-संचालित निवेश (एल.डी.आई.) संकट ने अत्यधिक परस्पर जुड़े वित्तीय ढांचे में अंतर्निहित

¹² वित्त वर्ष 2023-24 में एनबीएफसी के लिए बकाया सीपी में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट 2023-24)।

¹³ वित्त वर्ष 2023-24 में एनबीएफसी के लिए सुरक्षा रहित बकाया डिबेंचर में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट 2023-24)।

कमजोरियों को उजागर किया है, जहाँ एक खंड की विफलता कई क्षेत्रों में व्यापक चलनिधि चुनौतियों को जन्म दे सकती है। पारंपरिक देयता प्रबंधन मॉडल, जो अक्सर ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं, असाधारण बाजार स्थितियों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को पर्याप्त रूप से दर्शा नहीं पाते हैं। अतः, विनियमित संस्थाओं को चाहिए कि वे अधिक परिष्कृत दबाव-परीक्षण पद्धतियाँ विकसित करें जो चरम परिदृश्यों का सामना करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करती हों, जिसमें उन स्थितियों को भी शामिल किया जाए जो परस्पर जुड़े वित्तीय नेटवर्क में आघातों की तीव्रता को बढ़ाती हैं।

अंतिम बिंदु है - आकस्मिक निधि योजनाओं (सीएफपी) का महत्वा सामान्य तौर पर, आरई के पास उनकी अपनी जटिलता, जोखिम प्रोफाइल, संचालन के दायरे और वित्तीय प्रणाली में उनकी भूमिका के अनुरूप एक औपचारिक आकस्मिक निधि योजना होनी चाहिए। अन्य बातों के अलावा, उसमें उपलब्ध संभावित आकस्मिक निधि स्रोतों और इन स्रोतों से प्राप्त की जा सकने वाली निधियों की मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बैंकों के अंतिम उपाय के ऋणदाता (एलओएलआर) के रूप में कार्य को बैंकों के लिए चलनिधि आघातों से बचाने (अंतर्निहित) के लिए बीमा के रूप में माना जाता है, जिसे मुद्रा बाजार प्रतिभागी अवशोषित करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ होते हैं। इस बीमा का मूल्य बैंकों के चलनिधि जोखिम के साथ बढ़ता है, जिससे नैतिक जोखिम भी बढ़ता है। बैंकों को यह ध्यान में रखना होगा कि इस नैतिक जोखिम से निपटने के लिए, केंद्रीय बैंक यह निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं कि विशिष्ट संस्थानों को आपातकालीन चलनिधि सहायता प्रदान की जाए या नहीं। यह सहायता लोक निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए सुरक्षा जाल के रूप में अभिप्रेत है जो अक्सर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप और शर्तों के साथ होती है। इसलिए, एलओएलआर कार्य को आकस्मिक निधि के नियमित घटक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

जहाँ तक एनबीएफसी का सवाल है, वे ऋण उपलब्ध कराने और आर्थिक संवृद्धि को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों में परिपक्वता, चलनिधि और ऋण परिवर्तन की महत्वपूर्ण मात्रा भी शामिल होती है। बैंकों के विपरीत, अधिकांश एनबीएफसी के पास सार्वजनिक जमाराशियों तक पहुँच नहीं होती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विनियामक दृष्टिकोण एनबीएफसी की जमाराशि लेने की गतिविधियों को हतोत्साहित करने का रहा है। बैंकों के पास

आधिकारिक सुविधा की उपलब्धता और जमा संस्थाओं तक उनकी पहुँच है जिसके कारण उसने पास निधि के अधिक स्थिर खुदरा स्रोत हैं जबकि, एनबीएफसी अपनी निधि के लिए बैंकों और पूंजी बाजारों पर निर्भर रहेंगे। एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने निधि स्रोतों में विविधता लाएं, और उधार लेने की लागत को कम करें और एक स्थायी विकास पथ के लिए संबंधित जोखिमों को कम करें।

निष्कर्ष

आज, हम सामूहिक रूप से 2047 तक, अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक 'विकसित भारत' की आकांक्षा रखते हैं। इस महत्वाकांक्षा के लिए सतत और टिकाऊ आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ समुत्थानशीलता की प्रणालीगत क्षमता की आवश्यकता होती है। इस विजन के तहत महत्वाकांक्षी आर्थिक संवृद्धि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय आस्तियों और बैंक आस्तियों को अगले दो दशकों में लगातार और उच्च गति से विकास हासिल करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वित्तीय क्षेत्र के लिए

देयताओं और पूंजी में इसी तरह की वृद्धि की आवश्यकता होगी। इससे कुछ उभरती चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता सामने आती है क्योंकि ग्राहक व्यवहार और वरीयताएँ गहन परिवर्तनों से गुजर रही हैं जबकि वैश्विक पारितंत्र और बाहरी कारक, जैसे कि तीसरे पक्ष की निर्भरता, और प्रौद्योगिकी बदलाव तेजी से जटिल होते जा रहे हैं, जो व्यवसाय परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। सामूहिक रूप से, ये परिवर्तन आरई के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बना रहे हैं, जिससे आरई को अपने दृष्टिकोण और व्यावसायिक रणनीतियों को फिर से जांचने की आवश्यकता होगी। यह केवल जोखिमों के प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि निधि संरचनाओं को बेहतर बनाने, स्थिरता बढ़ाने और आर्थिक संवृद्धि का समर्थन करने के अवसरों का लाभ उठाने के बारे में भी है। 2047 तक "विकसित भारत" का मार्ग काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्तीय प्रणाली इन प्रवृत्तियों के साथ कितनी अच्छी तरह से अनुकूलन करती है और किस प्रकार संसाधन जुटाने और देयता प्रबंधन की जटिलताओं का प्रबंधन करती है।

धन्यवाद।